RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 16 OCTOBER TO 22 OCTOBER 2019 प्रति बुधवार वर्ष 05 अंक 8 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

दिसंबर तक चालू हो जायेगा मूंदड़ा एलएनजी टर्मिनल Page 3

फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन के फेस्टिव डिस्काउंट्स की जांच करेगी सरकार Page 4

बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, चेतक नाम से वापसी की तैयारी Page 7

editoria!

ग्लोबल सुस्ती

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी मान लिया है कि दुनिया स्लोडाउन की ओर जा रही है। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, जिसके कारण 90 फीसदी देशों की विकास की रफ्तार अगले साल धीमी रहेगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत और ब्राजील जैसे देशों में इसका असर सबसे ज्यादा देखा जाएगा। जॉर्जिएवा ने कहा कि तमाम विकसित देशों में आर्थी?क गतिविधियां लगातार कमजोर पड़ रही हैं। अमेरिका और जर्मनी में बेरोजगारी की दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, इसके बावजूद जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्थाएं नरमी का संकेत दे रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ रही है। पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे देशों के लिए ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी करने वाली हैं। इससे कई मुल्कों में आईएमएफ की परियोजनाएं भी फंस सकती हैं। अगले हफ्ते आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की संयुक्त सालाना बैठक होने वाली है जिसमें दोनों संस्थाएं अपने आर्थी?क अनुमान पेश करेंगी। सच कहें तो स्लोडाउन का अहसास सबको था, इसे लेकर चर्चाएं भी थीं लेकिन पहली बार किसी वैश्विक वित्तीय संगठन ने बाकायदा इसे स्वीकार किया है। एक तरह से यह अच्छा भी है क्योंकि बीमारी की स्वीकृति के बाद दुनिया मिलकर उसका इलाज खोजने में जुट सकती है। वर्ष 2009 के आसपास मंदी से निपटने का संयुक्त पराक्रम दिखाया जा चुका है, हालांकि तब और अब में एक बड़ा अंतर है। उस समय समस्या से निपटने के लिए सारे देश आपसी सहमति से कोई कदम उठाते थे लेकिन आज इसकी कल्पना भी कठिन लगती है। एक साथ कई सारे ट्रेड वॉर चल रहे हैं। विश्व की नंबर एक और दो अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन एक-दूसरे को बर्बाद करने में जुटे हैं। इसके समानांतर यूरोपियन यूनियन से भी अमेरिका की तकरार शुरू हो गई है। अपने पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको से लेकर पुराने सहयोगी भारत तक पर कई सख्त व्यापारिक शर्तें अमेरिका ने थोप दी हैं। ऐसे में किसी सामूहिक कदम की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जहां तक भारत का प्रश्न है, यहां भी कई अर्थशास्त्रियों ने बार-बार स्लोडाउन पर चिंता जताई है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि बाजार में मांग गिर गई है, निर्यात कम हुआ है, निवेश घटा है, नए रोजगार नहीं पैदा हो रहे, ये सारे लक्षण किसी गहरी समस्या के हैं। लेकिन सरकार इसे एक फौरी मामले से ज्यादा वजन देने को राजी नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी सवाल उठाया कि सरकार इस बात को मान क्यों नहीं रही। अच्छा होगा कि आईएमएफ की इस चेतावनी के बाद सरकार ही नहीं, उद्योग जगत भी आने वाली चुनौतियों के लिए कमर कस ले और अगले कुछ वर्षों के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाकर काम करे। अगर हम अब भी बेपरवाह रहे तो स्थितियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी।

IMF ने किया आगाह

11 साल बाद मंदी की ओर बढ़ती दुनिया, भारत के लिए थोड़ी राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) International Monetary Fund की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक World Economic Outlook की रिपोर्ट चौंकानी वाली है। इस रिपोर्ट में दुनियाभर में आर्थिक मंदी की आशंका जाहिर की गई है। तरह-तरह के ट्रेड बैरियर और भू-राजनीतिक चिंताओं के चलते ग्लोबल इकोनॉमी एक 'सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाउन' के चक्र में फंसी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट। इसका भारत से क्या है लिंक।

11 साल बाद IMF की चिंताजनक रिपोर्ट

आइएमएफ ने 2019 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर का अनुमान घटाकर तीन फीसद कर दिया है। 2008 में आई मंदी के बाद से यह ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे कम विकास दर होगी। इस मामले में भारत को भी लेकर सजग किया गया है। भारत के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसके राजस्व अनुमान आशावादी लग रहे हैं।

सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत

आइएमएफ ने भारत की विकास दर का अनुमान भी घटाया है। हालांकि वैश्विक परिस्थिति में भारत कम विकास दर के साथ भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.1 फीसद रखा गया है। इस साल अप्रैल में आइएमएफ ने 7.3 फीसद की विकास दर का अनुमान दिया था। जुलाई में इसे मामूली कम करते हुए विकास दर सात फीसद पर रहने का अनुमान जताया गया था। अच्छी खबर यह है कि आइएमएफ ने अगले साल भारत की विकास दर फिर सात फीसद रहने का अनुमान दिया है। इस दौरान चीन की विकास दर 5.8 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है।

ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर तीन फीसद पर पहुंची

आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि 2017 के 3.8 फीसद की तुलना में ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर तीन फीसद पर पहुंचना चिंताजनक है। सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाउन और अनिश्चित हालात के कारण ग्लोबल आउटलुक कमजोर है। तीन फीसद की विकास दर को देखते हुए नीति निर्माताओं के पास अनदेखी का कोई विकल्प नहीं है। सभी देशों के नीति निर्माताओं को मिलकर कारोबारी एवं अन्य राजनीतिक चिंताओं को दूर करना होगा। आइएमएफ ने 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर 3.4 फीसद रहने का अनुमान जताया है। गोपीनाथ ने कहा कि इस गिरावट के पीछे कुछ कारण काम कर रहे हैं।

चीन और अमेरिका पर टिकी निगाह

यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका और चीन 2018 की शुरुआत में एक-दूसरे पर लगाए गए शुल्क हटा दें, तो ग्लोबल इकोनॉमी में 2020 तक 0.8 फीसद की वृद्धि हो सकती है। दरअसल, ऊंचे शुल्क और व्यापार नीतियों पर लंबे समय से अनिश्चितता के माहौल ने निवेश को नुकसान पहुंचाया है। कैपिटल गुड्स की मांग पर भी इससे असर पड़ा है।

ब्रेक्जिट के कारण उपजा संकट

आइएमएफ ने चेताया है कि ब्रेक्जिट के कारण उपजे संकट और कई तरह के ट्रेड प्रतिबंध से सप्लाई चेन और कारोबारियों के भरोसे पर बुरा असर पड़ा है। गोपीनाथ ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे भी अब दिखने लगे हैं। अगर समय रहते नहीं निपटा गया, तो भविष्य में इनका भी व्यापक असर देखने को मिल सकता है।

सुस्ती का दौर से गुजर रही है विकसित मुल्कों की अर्थव्यवस्था

आइएमएफ का कहना है कि दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2019 और 2020 में 1.7 फीसद पर रहने का अनुमान है। वहीं, विकासशील व उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2019 में 3.9 फीसद और 2020 में 4.6 फीसद रहने का अनुमान है। यूरो क्षेत्र की विकास दर इस साल 1.2 फीसद और अगले साल 1.4 फीसद रहने का अनुमान है। जर्मन इकोनॉमी की विकास दर मात्र आधा फीसद रहेगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस साल 2.1 फीसद और अगले साल 2.4 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान है।

इंडियन प्लास्ट पैक फोरम की नई कार्यकारिणी घोषित

अध्यक्ष सचिन बंसल और सचिव राठी बने

इंदौर। प्रदेश के प्लास्टिक उद्योगों के सबसे बडा संगठन इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के द्विवर्षीय चुनाव में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। चुनाव में निर्विरोध घोषित नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष श्री सचिन बंसल और सचिव श्री रामकिशोर राठी बनाए गए। साथ ही उपाध्यक्ष के पद पर श्री प्रमोद सोमानी, श्री किशोर वैद्य और श्री मेहुल ठक्कर को मनोनित किया गया।

कार्यकारिणी में सह सचिव श्री शोभित बर्मन, कोषाध्यक्ष श्री विकास बांगड और कन्वेयर वरिष्ठ सदस्य श्री हितेश मेहता मेहता को बनाया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया कि प्लास्टिक उद्योगों की समस्याओं और उद्योग के सामने खडें सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसी समस्याओं का शासन के साथ मिल कर गतिरोध दूर करने का प्रयास किया जाएगा। संगठन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उन्होनें कहा कि उद्योग हित में हर संभव प्रयास किया जाएगा। नवनिर्वाचित आईपीपीएफ टीम को अनेक औद्योगिक संगठन और वरिष्ठ उद्योगपतियों और राष्ट्रीय और प्रदेशीत स्तर के अन्य औद्योगिक संगठनों ने शुभकामानऐं दी।

अडाणी गैस में 37.4 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी फ्रांस की टोटल

नयी दिल्ली। एजेंसी

फ्रांस की ऊर्जा कंपनी टोटल एसए ने अडाणी गैस लि. में 37.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की। कंपनी यह हिस्सेदारी करीब 5,700 करोड़ रुपये में खरीदेगी। अडाणी गैस लि. वाहनों और घरों में गैस की आपूर्ति करती है। टोटल ने पिछले साल अक्टूबर में अडाणी के दो एलएनजी आयात टर्मिनल के साथ देश में अगले 10 साल में 1,500 पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिये 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम बनाया था। इससे पहले, कंपनी अगस्त 2018 में गुजरात के हजीरा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल में रॉयल डच के साथ संयुक्त उद्यम से हट गयी थी। अडाणी समूह ने एक अलग बयान में कहा कि शहरों में गैस वितरण दोनों भागीदारों की बुनियादी ढांचा और संपत्ति में एक अरब डॉलर से अधिक के निवेश की योजनाओं का एक स्वभाविक विस्तार है। यह निवेश एलएनजी बुनियादी ढांचा और विपणन तथा ईंधन के खुदरा कारोबार तक फैला है। टोटल सबसे पहले अडाणी गैस में 25.2 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिये खुली पेशकश करेगी। खुली पेशकश में सफलता के आधार पर वह अडाणी में हिस्सेदारी लेगी। इससे टोटाल की अडाणी गैस में हिस्सेदारी 37.4 प्रतिशत हो जाएगी। अडाणी परिवार के पास अडाणी गैस में 74.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दोनों कंपनियों के संयुक्त बयान के अनुसार अडाणी सार्वजनिक तौर पर हिस्सेदारी बेचकर उसे 37.4 प्रतिशत पर लाएगी। यह टोटल की हिस्सेदारी के बराबर होगी।

भारत की ओपेक देशों से तेल उत्पादन में कटौती नहीं करने, बेहतर व्यापार शर्तों की मांग

नयी दिल्ली। एजेंसी

अर्थव्यवस्था में सुस्ती से जूझ रहे भारत ने मंगलवार को कच्चे तेल के तर्कसंगत दाम और आपूर्ति में स्थायित्व की अपनी मांग को एक बार फिर उठाते हुये तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से कहा है कि वह कच्चे तेल के उत्पादन में बड़ी कटौती नहीं करे। ओपेक महासचिव मोहम्मद सनुशी बारकिंडो से मुलाकात के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कच्चे तेल के आयात के मामले में बेहतर वाणिज्यिक शर्तों पर भी जोर दिया। उन्होंने कच्चे तेल के आधिकारिक बिक्री मूल्य, भुगतान अवधि को माल लदान के दिन से मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने, भाड़े में रियायत और भारतीय तेल कंपनियों की साख को देखते हुये खुली रिण सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर भी जोर दिया। बैठक के बाद प्रधान ने

संवाददाताओं से कहा, "हमने मौजूदा तेल उपलब्धता परिदृश्य को लेकर बातचीत की।" तेल निर्यातक देशों का संगठन अपनी नीतियों को तय करने से पहले उपभोक्ताओं की रुचि के बारे में भी जानकारी ले रहा है। उन्होंने कहा कि ओपेक देशों की दिसंबर में बैठक होगी और उम्मीद है कि संगठन तल उत्पादन में किसी नई कटौती के बारे में घोषणा नहीं करेगा। प्रधान ने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत की आवाज अब विश्व स्तर पर सुनी जा रही है। ओपेक महासचिव भारत की आवाज को तेल उत्पादक देशों की बैठक में पहुंचायेगे। इराक और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक देशों से भारत की तेल जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आपूर्ति करते हैं। इन देशों द्वारा उत्पादन में किसी भी तरह की कटौती से दाम बढ़ जायेंगे और अर्थव्यवस्था में सुस्ती का सामना कर रहे देश के लिये इससे निपटना मुश्किल होगा।

देश का सेवा निर्यात अगस्त महीने में 10 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई। एजेंसी

भारत का सेवा निर्यात चालू वित्त वर्ष के अगस्त महीने में 10.4 प्रतिशत बढ़कर 18.24 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा निर्यात या प्राप्ति 2018 के इसी महीने में 16.53 अरब डॉलर थी। इस साल जुलाई में यह 19.08 अरब डॉलर था।केंद्रीय बैंक के भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा निर्यात पर मासिक आंकड़ों के अनुसार सेवा आयात या भुगतान अगस्त 2019 में 12 अरब डॉलर रहा जो पिछले साल के इसी महीने के 10.35 अरब डॉलर के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। सेवा आयात जुलाई महीने में 12.83 अरब डॉलर था। आरबीआई का सेवा पर मासिक आंकड़ा अस्थायी है और तिमाही आधार पर भुगतान संतुलन का आंकड़ा जारी होने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी।

ओएनजीसी ने अपतटीय क्षेत्रों के विकास के लिये एक्सोन के साथ समझौते पर किये दस्तखत

नयी दिल्ली। ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज वैश्विक कंपनी एक्सोन मोबिल सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को पूर्वी और पश्चिमी तटों खासकर गहरे समुद्री क्षेत्र में तेल एवं गैस संसाधनों के विकास में मदद करेगी। ओएनजीसी ने अमेरिकी कंपनी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, "इस सहमति पत्र से दोनों पेट्रोलियम कंपनियां संयुक्त तकनीकी अध्ययन कर सकेंगी और पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गहरे जल क्षेत्रों तथा पेट्रोलियम खोज लाइसेंस ब्लाक के साथ खुले क्षेत्र के लिये संयुक्त बोली के लिये सहयोग कर पाएंगी।" आईएचएस-सेरावीक कार्यक्रम के दौरान सहमति पत्र पर ओएनजीसी के निदेशक (खोज) आर के श्रीवास्तव ओर एक्सोन मोबिल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दक्षिण एशिया) विलियम पी डेविस ने सोमवार को दस्तखत किये। इस मौके पर ओएनजीसी के चेयरमेन शशि शंकर भी मौजूद थे। बयान के अनुसार, "सहमति पत्र के तहत कार्य तीन चरणों में किया जाएगा। इससे संभावित सहयोग वाले क्षेत्रों के लिये संयुक्त तकनीकी अध्ययन हो सकेगा।" ओएनजीसी के ब्लाक का अध्ययन करने के बाद पक्का करार किया जाएगा।

दिसंबर तक चालू हो जायेगा मूंदड़ा एलएनजी टर्मिनल

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

गुजरात सरकार समर्थित मूंदड़ा एलएनजी परियोजना दिसंबर तक चालू हो सकती है। करीब 5,500 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का उद्घाटन एक साल पहले ही हो चुका है लेकिन विभिन्न कारणों से यह अब तक चालू नहीं हो पाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।परियोजना के भागीदार गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) और अडाणी ग्रुप के बीच विवाद की वजह से 50 लाख टन सालाना क्षमता वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात सुविधा के चालू होने पर रोक लगी थी। टर्मिनल 2018 के मध्य में बनकर तैयार हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।हालांकि, प्रवर्तकों और गुजरात सरकार के बीच कुछ पट्टों और समझौतों को अंतिम रूप देने में देरी हुई जिसके कारण इसे चालू नहीं किया जा सका। सूत्रों के अनुसार पिछले साल नवंबर में मूंदड़ा एलएनजी टर्मिनल पर अमेरिका से एक मालवाहक जहाज पहुंचा था लेकिन उसे मूंदड़ा पर अनुमति नहीं दी गयी और उसे हजीरा भेज दिया गया। जीएसपीसी और राज्य की इकाइयों की जीएसपीसी एलएनजी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जीएसपीएल एलएनजी ने टर्मिनल का निर्माण किया है। अडाणी समूह की

कंपनी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि शेष हिस्सेदारी रणनीतिक निवेशक / ईंधन आपूर्तिकर्ता / वित्तीय संस्थान और आम निवेशक हैं। क्रायोजेनिक जहाजों में प्राकृतिक गैस (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) के आयात और इसे ग्राहकों को पाइप के जरिये आपूर्ति से पहले गैसीय अवस्था में बदलने को लेकर मूंदड़ा गुजरात में तीसरा आयात टर्मिनल है।

गेल के विभाजन पर विचार करेगा मंत्रिमंडल

2022 से पहले नहीं बेचा जाएगा पाइपलाइन कारोबार

नयी दिल्ली।एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के पाइपलाइन कारोबार को अलग करके एक पृथक इकाई बनाने के प्रस्ताव पर अगले महीने तक विचार कर सकता है। हालांकि , रणनीतिक निवेशक को इसकी बिक्री 2022 से पहले नहीं की जाएगी। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। गेल देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस विपणन कंपनी है। देश के 16,234 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का दो - तिहाई से अधिक का स्वामित्व उसके पास है। प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सूत्रों ने बताया कि एक ही कंपनी के पास दोनों कारोबार होने की वजह से पैदा हो रही इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए गेल के विभाजन पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि गेल के पाइपलाइन कारोबार को अलग करके नई इकाई बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव पर इस महीने या नवंबर तक विचार कर सकता है या मंजूरी दे सकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद , पाइपलाइन कारोबार को एक अलग अनुषंगी इकाई में स्थानांतरित करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 8-10 महीने का समय लगेगा। हालांकि , पाइपलाइन कारोबार वाली अनुषंगी कंपनी को रणनीतिक निवेशक को 2022 से पहले नहीं बेचा जा सकता है क्योंकि सरकार का मानना है कि गैस बाजार इससे पहले परिपक्व नहीं होगा और गेल को राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण करने के लिए सरकार के समर्थन की जरूरत होगी।

रॉ मैटीरियल इंपोर्ट से पहले एक्सपोर्ट पर GST छूट के लिए DRI का नोटिस

मुंबई। एजेंसी

एक्सपोर्टर्स ने जिन मामलों में इंपोर्ट से पहले एक्सपोर्ट करके गलत तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स छूट ली है, उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे मामलों में गुजरात हाईकोर्ट के एक और ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिए जाने के कुछ दिन बाद ये नोटिस जारी हुए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था जिसमें DRI को उन एक्सपोर्टर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की इजाजत दी गई थी, जिन्होंने इंपोर्ट से पहले की शर्त का पालन नहीं किया था और गलत तरीके से GST छूट ली थी।

कई एक्सपोर्टर्स को ध्ठएऊ लौटाना पड़ सकता है और उन पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि DRI की तरफ से जिस तरह टैक्स नोटिस जारी हो रहे हैं, उससे लगता है कि कर विभाग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार नहीं करना चाहता। नोटिस उन एक्सपोर्टर्स को भेजे जा रहे हैं जिन्होंने पहले माल विदेश भेजा और बाद में कच्चा माल मंगाया था लेकिन उएऊ टैक्स में छूट का फायदा ले लिया। लगभग 1,000 एक्सपोर्टर्स को ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं।

इस केस में कुछ एक्सपोर्टर्स की पैरवी कर रही खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक ए रस्तोगी कहते हैं, 'एक्सपोर्टर्स को कारण बताओ नोटिस पर रोक के लिए संबंधित हाईकोर्ट में जाना होगा और राहत हासिल करनी होगी।' एक्सपोर्टर्स से पहले IGST चुकाने के लिए कहा गया है क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पिछले कुछ महीनों में कई तरह के संशोधन किए गए हैं और कई नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। ईटी ने 10 अक्टूबर को एक एक्सपोर्टर को जारी हुए नोटिस देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर 4 अक्टूबर को रोक लगा दी थी।

एक्सपोर्टर्स को विदेश से सामान मंगाते ही ध्ठएऊ देना होगा, जिसकी दर 18%, 12% और 5% है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि पिछली टैक्स व्यवस्था और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) में इंपोर्टेड रॉ मैटीरियल का इस्तेमाल एक्सपोर्ट में होने पर कोई ड्यूटी नहीं देनी होती थी। यह सुविधा इंपोर्ट से पहले एक्सपोर्ट किए जाने के समय भी थी। हालांकि जीएसटी फ्रेमवर्क में एक्सपोर्टर्स को कुछ बेनेफिट्स हासिल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है।

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक बेनेफिट के लिए रॉ मैटीरियल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद नहीं हो सकता। सरकार ने GST फ्रेमवर्क में संशोधन किया है जिसके आधार पर DRI ने एक्सपोर्टर्स को नोटिस जारी करना शुरू किया है। संशोधन में साफ कहा गया है कि इंपोर्ट ड्यूटी में छूट के लिए हर एक्सपोर्टर को इंपोर्ट पहले करना होगा। नोटिस के मुताबिक, 'जिन मामलों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पहले हुआ है उनमें ली गई टैक्स छूट कानूनी तौर पर सही और उचित नहीं है।'

वित्त मंत्री से एटीएफ, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की अपील

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की अपील की है। क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के करों से राहत देने तथा व्यापार माहौल में सुधार के इरादे से उन्होंने यह बात कही। एक जुलाई 2017 में जीएसटी पेश किये जाने के बाद एक दर्जन से अधिक केंद्रीय एवं राज्य करों को इसमें समाहित किया गया लेकिन पांच जिंसों... कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) को इसके दायरे से बाहर रखा गया। इसके लिये राज्य सरकारों की राजस्व के लिये इन वस्तुओं पर निर्भरता का हवाला दिया गया। सेरा वीक के इंडिया एनर्जी फोरम में उन्होंने कहा, ''जीएसटी लागू हुए दो साल से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान पेट्रोलियम उद्योग से सभी पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की लगातार मांग हो रही है।'' उन्होंने कहा, ''मैं वित्त मंत्री से इस मामले को जीएसटी परिषद के समक्ष उठाने की अपील करता हूं और कम-से-कम प्राकृतिक गैस और एटीएफ को इसके दायरे में लाकर शुरूआत करने का आग्रह करता हूं।'' सम्मेलन में सीतारमण को भी शामिल होना था लेकिन प्रधान के संबोधन के समय वह नहीं पहुंच पायी। प्रधान ने कहा, ''पेट्रोलियम क्षेत्र की जटिलता और राजस्व के नजरिये से राज्य सरकारों की इस क्षेत्र पर निर्भरता को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के दायरे से बाहर रखा गया है।'' एटीएफ और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने से कंपनियों को कच्चे माल पर दिये जाने वाले कर से राहत मिलेगी बल्कि ईंधन पर कराधान के मामले में एकरूपता आएगी। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद इस मामले में उपयुक्त समय पर निर्णय करेगी। परिषद निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है।

तेल, गैस क्षेत्र में अगले कुछ साल में 118 अरब डॉलर का होगा निवेशः प्रधान

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में अगले कुछ साल में तेल, गैस खोज एवं उत्पादन के साथ प्राकृतिक गैस ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में 118 अरब डॉलर का निवेश होने जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने की तैयारी में है।उन्होंने कहा कि इस निवेश में से तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन में 2023 तक 58 अरब डॉलर का निवेश जबकि पाइपलाइन, आयात टर्मिनल और शहर में गैस वितरण नेटवर्क जैसी प्राकृतिक गैस ढांचागत सुविधाओं में 2024 तक 60 अरब डॉलर का निवेश होगा।

सेरा वीक के इंडियन एनर्जी फोरम सम्मेलन में प्रधान ने कहा कि देश में ऊर्जा स्तर में जो बदलाव आ रहा है वह वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ''भारत आज दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत आने वाले दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग के लिहाज से प्रमुख देश होगा।''प्रधान ने कहा कि भारत निवेश के लिये स्थिर राजनीति के साथ सुधार उन्मुख रुख तथा मजबूत संस्थागत रूपरेखा की पेशकश करता है।

मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने तेल एवं गैस माहौल को बेहतर बनाने के लिये नीतिगत रूपरेखा में व्यापक बदलाव लाया है और अनुकूल व्यापार माहौल स्थापित किया है। उन्होंने कहा, ''सऊदी अरामको, एडीएनओसी, बीपी, शेल, टोटनल, रोसनेफ्ट और एक्सोनमोबिल जैसी दुनिया की प्रमुख तेल एवं गैस कंपनी की भारत में बढ़ती मौजूदगी देश के प्रति वैश्विक निवेशकों के भरोसे की गवाह है...।''निवेश के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान ने कहा कि खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत तीन दौर की बोलियां और खोजे गये छोटे फील्डों के विकास की नीति के अंतर्गत दो दौर की बोलियों से कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन में 2023 तक करीब 58 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है।'' गैस के बारे में उन्होंने कहा, ''इसके अलावा गैस पाइपलाइन, टर्मिनल और शहर गैस ढांचागत सुविधाओं में 60 अरब डॉलर का निवेश अनुमानित है। ये सभी क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।'' प्रधान ने कहा कि हालांकि भारत में वैश्विक औसत से प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम है लेकिन इसके बावजूद देश कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने को लेकर प्रतिबद्ध है।

IMF का अनुमान

सारी दुनिया के साथ भारत में भी मुश्किल दौर में अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) का कहना है कि एक दशक पहले आए वित्तीय संकट के बाद पहली बार सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी सुस्त दिखाई दे रही है। मुद्राकोष का अनुमान है कि इस साल सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर मात्र 3 प्रतिशत का विकास होगा। वहीं भारत में इस साल विकास दर घटकर 6.1 प्रतिशत रह जाएगी। आईएमएफ़ ने इससे पहले इसी साल अप्रैल में भारत की विकास दर के 7.3 फीसदी रहने की बात की थी।

फिर जुलाई में संस्था ने भारत के लिए अपने अनुमान को घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। वैश्विक आर्थिक सुस्ती का भारत पर असर आईएमएफ़ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कटौती करते हुए 2019-2020 के लिए इसे घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि मुद्रा कोष ने 2020-21 में इसमें कुछ सुधार की उम्मीद भी जताई है। आईएमएफ़ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि '2020 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कुछ बढ़कर सात प्रतिशत तक होने की उम्मीद की जा रही है।' आईएमएफ़ ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा 'कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की कमज़ोरी और उपभोक्ता और छोटे और मध्यम दर्जे के व्यवसायों की ऋण लेने की क्षमता पर पड़े नकारात्मक असर के कारण भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कमी आई है।' उनका कहना था कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम कर रही है, लेकिन भारत को अपने राजकोषीय घाटे पर लगाम लगानी होगी। आईएमएफ़ के मुताबिक़ लगातार घटती विकास दर का कारण घरेलू मांग का उम्मीद से ज्यादा कमज़ोर रहना है। आईएमएफ़ ने चीन के लिए इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.1 फीसदी और 2020 में 5.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 फीसदी थी।

वैश्विक विकास दर में भी कमी

आईएमएफ़ के अनुसार वैश्विक विकास दर इस साल मात्र 3 प्रतिशत ही होगी लेकिन इसके 2020 में 3.4 तक रहने की उम्मीद है। आईएमएफ़ ने यह भी कहा, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है और हम 2019 के विकास दर को एक बार फिर से घटाकर 3 प्रतिशत पर ले जा रहे हैं जो कि दशक भर पहले आए संकट के बाद से अब तक के सबसे कम है। ये जुलाई के वैश्विक विकास दर के उसके अनुमान से भी कम है. जुलाई में यह 3.2 फीसद बताई गई थी। आईएमएफ़ ने कहा, 'आर्थिक वृद्धि दरों में आई कमी के पीछे विनिर्माण क्षेत्र और वैश्विक व्यापार में गिरावट, आयात करों में बढ़ोतरी और उत्पादन की मांग बड़े कारण हैं।' आईएमएफ़ ने कहा इस समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माताओं को व्यापार में रूकावटें खत्म करनी होंगी, समझौतों पर फिर से काम शुरू करना होगा और साथ ही देशों के बीच तनाव कम करने के साथ-साथ घरेलू नीतियों में अनिश्चितता खत्म करनी होगी।

दुनिया के कई देशों पर होगा असर?

आईएमएफ़ का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के कारण इस साल दुनिया के 90 प्रतिशत देशों में वृद्धि दर कम ही रहेगी। आईएमएफ़ ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में तेजी से 3.4 फीसद तक जा सकती है। हालांकि इसके लिए उसने कई खतरों की चेतावनी भी दी है क्योंकि यह वृद्धि भारत में आर्थिक सुधार पर निर्भर होने के साथ-साथ वर्तमान में गंभीर संकट से जूझ रही अर्जेंटीना, तुर्की और ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती है। उन्होंने कहा, 'इस समय पर कोई भी गलत नीति जैसे कि नो-डील ब्रेक्सिट या व्यापार विवादों को और गहरा करना, विकास और रोज़गार सृजन के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। आईएमएफ के अनुसार कई मामलों में सबसे बड़ी प्राथमिकता अनिश्चितता या विकास के लिए खतरों को दूर करना है।

फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन के फेस्टिव डिस्काउंट्स की जांच करेगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

इस साल फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट तथा ऐमजॉन द्वारा दिए गए भारी-भरकम डिस्काउंट की सरकार जांच करेगी कि उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने ऑफलाइन कारोबार करने वाले 13 करोड़ कारोबारियों को बड़े ऑनलाइन डिस्काउंट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फरवरी में FDI के नियमों में बदलाव किया था। नियमों में बदलाव की वजह से ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने बिजनस स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ा था। सरकार के कदम की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद भारत तथा अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी।

सेल्स कमिशन कम करने की पेशकश

ऐमजॉन तथा फ्लिपकार्ट का कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया है, जबकि स्थानीय कारोबारी संगठनों ने कहा है कि फेस्टिव सीजन को लेकर चल रहे ऑनलाइन सेल में भारी-भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है और

किसी-किसी मामले में यह 50इ से भी अधिक है। फ्लिपकार्ट द्वारा सेलर्स को भेजे गए ई-मेल तथा ट्रेनिंग मटीरियल्स को देखा है, जिसमें उसने डिस्काउंट पर सामान बेचने वाले सेलर्स से मिलने वाले सेल्स कमिशन को कम करने की पेशकश की है।

फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन के खिलाफ सबूत दिए

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि 70 लाख ऑफलाइन रिटेलरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (ष्ष्ष्ऊ) ने ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें की हैं और उनके खिलाफ सबूत भी दिया है। सीएआईटी ने आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।

कंपनियों ने किया इनकार

अधिकारी ने ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा संभावित कार्रवाई पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, हालांकि मामले पर चर्चा करने के लिए ऐमजॉन तथा फ्लिपकार्ट के अधिकारियों को पिछले सप्ताह वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया गया था। फ्लिपकार्ट ने एक बयान जारी कर कहा है कि अधिकारियों के साथ उनकी 'बैठक अच्छी' रही और वह भारत में 'कानूनी तरीके से कारोबार करने को लेकर प्रतिबद्ध है।' वहीं, ऐमजॉन ने कहा कि अधिकारियों के साथ उसकी बैठक खुली और पारदर्शी रही और वह नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ऑफलाइन बिक्री में 40% की गिरावट

सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, 'ग्राहक खरीदारी के लिए ई-कॉमर्स का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने ऑफलाइन बिजनस में 30-40% की गिरावट आई है।'

1 नवंबर से बदल जाएगा SBI का यह नियम

42 करोड़ ग्राहकों पर होगा सीधा असर

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल एसबीआई ने सेविंग बैंक डिपॉजिट, होम-ऑटो लोन और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा दी हैं। बैंक के इस फैसले से करीब 42 करोड़ ग्राहक प्रभावित होंगे। बैंक ने सेविंग बैंक डिपॉजिट की ब्याज दरें कम कर दी हैं। एँ्ड अभी तक सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा रखने वालों को 3.50 फीसदी के हिसाब से ब्याज देता है, लेकिन अब वह ग्राहकों को 3.25 फीसदी के हिसाब से ब्याज देगा। नई दरें 1 नवंबर, 2019 से लागू होंगी।

होम-ऑटो और पर्सनल लोन होगा सस्ता

बैंक ने 10 अक्टूबर से एमसीएलआर की दरें 0.10 फीसदी तक घटा दी है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें 0.25 फीसदी घटाने का ऐलान किया है। रेपो रेट 0.25 फीसदी घटकर 5.15 फीसदी पर आ गई है। एसबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फेस्टिवल के मौके पर ग्राहकों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बैंक ने सभी अवधि के लिए एमसीएलआर दरें 0.10 फीसदी तक घटा दी हैं। अब एक साल के लिए नई एमसीएलआर दरें 8.15 फीसदी से घटकर 8.05 फीसदी पर आ गई है। नई दरें 10 अक्टूबर से लागू हो गई हैं।

FD पर भी घटाई ब्याज दर

बैंक ने एक से दो साल की अवधि के रिटेल टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और बल्क टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में भी कमी की है। एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर में 10 बेसिस प्वाइंट की कमी की है। वहीं बल्क टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर में 30 बेसिस प्वाइंट की कमी की गई है। इस टर्म डिपॉजिट की मियाद एक साल से दो साल तक की है। नई ब्याज दर 10 अक्तूबर से प्रभावी हो गई है।

कितनी तेजी से तकनीकी बदलाव लागू करता है भारत, क्या है रैंकिंग?

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अकसर यह सवाल उठता है कि दुनिया में होने वाले तकनीकी बदलावों को कौन-सा देश सबसे पहले स्वीकार करता है या उसे अपने सिस्टम में जल्द से जल्द लागू करता है। इसे लेकर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का एक सर्वे सामने आया है जिसमें भारत की रैंकिंग 25वीं है और टॉप पर अमेरिका है। भारत की रैंक वैश्विक ऐवरेज से अच्छी है। सबसे तेज गति से बदलाव लागू करने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है, सऊदी अरब 11वें पायदान पर है और भारत 25वें। तुर्की को 45वां रैंक मिला है और साउथ अफ्रीका को 73वां। ब्राजील इस लिस्ट में 11वें नंबर पर है।

आरबीआई यूनियन ने कहा, सहकारी बैंकों को शीर्ष बैंक के नियंत्रण में लाया जाए

मुंबई। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के संगठन ने शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरा अधिकार क्षेत्र समाप्त करने और उसे आरबीआई के दायरे में लाने का बुधवार को सुझाव दिया। पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में घोटाले के मद्देनजर अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने यह बात कही। यूनियन ने यह भी कहा कि आरबीआई को सभी सहकारी बैंकों की मौके पर जाकर निगरानी करनी चाहिए। फिलहाल इनकी निगरानी सालाना आधार पर दूर बैठकर की जाती है। आरबीआई द्वारा पीएमसी में जनवरी से वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने के बाद से बैंक 23 सितंबर से नियामकीय पाबंदी के दायरे में है। केंद्रीय बैंक ने 24 सहकारी बैंकों को अपने प्रशासक के अंतर्गत लाया है। यूनियन ने कहा, ''शहरी सहकारी बैंकों पर राज्यों की सहकारी समिति पंजीयक और आरबीआई का नियंत्रण है। यह दोहरा नियंत्रण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इस दोहरे नियंत्रण से कुप्रबंधन की गुंजाइश बनती है। इन सहकारी बैंकों को बैंकों की तरह आरबीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए।'' शहरी सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रूप में राज्य सहकारी समिति कानून या बहु-राज्य सहकारी समिति कानून, 2002 के तहत पंजीकृत हैं। वे राज्यों की सहकारी समिति पंजीयक या सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द्वारा नियंत्रित होते हैं। आरबीआई केवल उनके बैंक संबंधी कार्यों का नियमन और निगरानी करता है और फलस्वरूप प्रबंधन पर नियंत्रण कम होता है। यूनियन ने कहा, ''सभी सहकारी बैंकों खासकर उनके मुख्यालयों को आरबीआई के मौके पर जाकर निगरानी के दायरे में लाया जाना चाहिए। दूर से ही निगरानी की मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए क्योंकि धोखाधड़ी का पता लगाने में नियामक विफल रहा।'' पिछले महीने आरबीआई ने पीएसमी पर छह महीने की प्रतिबंध लगाया। बैंक द्वारा रीयल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को अपने कुल कर्ज का 73 प्रतिशत (6,500 करोड़ रुपये) ऋण देने की बात पाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया। बैंक ने यह कर्ज बिना उचित जांच पड़ताल के दी और वास्तविक कर्ज तथा एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) को छिपाया गया।

अधिक उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए कॉफी की खपत बढ़ाएं : वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कॉफी की पैदावार ज्यादा होने से इस समय इसकी कीमतों में नरमी का दबाव पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए इसकी खपत बढ़ाने जैसे कदम उठाने होंगे। वाणिज्य सचिव अनूप वाधवान ने यह बात कही।वाधवान ने कहा कि दुनिया के कॉफी व्यापार में भारत की छोटी ही सही लेकिन अहम भूमिका है। एक प्राथमिक उत्पाद के चलते यह हमेशा कीमतों के दबाव का सामना करने वाली जिंस है। इससे उत्पादन की विविधता प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, '' आज हम दुनिया में अधिक उत्पादन (कॉफी) की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उत्पादन आधिक्य का असर कीमतों में दबाव के रूप में देखने को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र के अन्य प्राथमिक उत्पादों की तरह इस क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन हमेशा वरदान नहीं होता।'' वह यहां कॉफी पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू और वैश्विक स्तर की चुनौतियों से वाकिफ है। कॉफी बोर्ड जैसे कई संगठन इससे प्रक्रियाबद्ध तरीके से निपटने का काम कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कॉफी बोर्ड को भारतीय कॉफी को दुनिया में पहचाने जाने वाला ब्रांड बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। सचिव वाधवान ने कहा कि किसान सबसे अधिक दबाव में रहता है। हमें किसान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की जरूरत है और इसका एक तरीका यह है कि मूल्यवर्द्धन श्रृंखला को उसके पास ले जाया जाए। इसके अलावा एक और चीज हमें इसका उपभोग बढ़ाने के बारे में जागरुकता पैदा करने की है। यह अधिक उत्पादन की समस्या से निपटने में मदद करेगा। भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक है। भारत बेंगलुरू में विश्व कॉफी सम्मेलन और प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा।

भारतीय तेल कारोबारियों ने रोकी मलयेशिया से पाम ऑइल की खरीद

कश्मीर पर पाक के पक्ष में बोले मलेशिया के पीएम

नई दिल्ली। एजेंसी

कश्मीर मसले को लेकर मलयेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा भारत की आलोचना से नाराज भारतीय कारोबारियों ने मलयेशिया से पाम ऑइल आयात के नए सौदे करना बंद कर दिया है। हालांकि, भारत सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन घरेलू खाद्य तेल उद्योग ने मलयेशिया को कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। खाद्य तेल उद्योग संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि देश पहले आता है और कारोबारी संबंध बाद में।

भारतीय कारोबारियों ने पाम ऑइल का आयात रोका

कश्मीर मसले पर भारत विरोधी बयान को लेकर देश के तेल कारोबारी मलयेशिया से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने अगले महीने के लिए होने वाले पाम तेल आयात के सौदों को

रोक दिया है। सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डॉ. बी. वी. मेहता ने कहा, 'हमारे लिए देश पहले आता है और कारोबारी संबंध बाद में। मलयेशिया से पाम तेल आयात करना हमारी मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि मलयेशिया की जगह इंडोनेशिया से पाम तेल ऑइल के हमारे विकल्प खुले हुए हैं।'

भारत सरकार मलयेशिया से आयात पर बढ़ा सकती है टैरिफ

डॉ. मेहता ने कहा, 'भारत, मलयेशिया के पाम ऑइल का सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन मलयेशिया से आयात रुकने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम इसके बदले इंडोनेशिया से इसका आयात कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि भारत सरकार मलयेशिया से पाम ऑइल का आयात रोकने के लिए आयात शुल्क में वृद्धि कर सकती है या फिर कोटा निर्धारित कर सकती है। लेकिन, सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

सबसे ज्यादा मलयेशिया से ही पाम तेल का आयात करता है भारत

मलयेशिया पाम ऑइल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, मलयेशिया ने इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान सिर्फ 9 महीने में 39,08,212 टन पाम ऑइल भारत को निर्यात किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसने भारत को 18,88,216 टन तेल बेचा था। मतलब इस साल भारत ने पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी अधिक तेल खरीदा है।

प्याय की कीमत में स्थिरता, गिरावट का रुख दिख रहा है: सरकारी समिति

नयी दिल्ली। एजेंसी

आवश्यक जिंसों की कीमतों की समीक्षा करने के बाद सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्याज की कीमतों में तेजी थम गयी है और अब गर्मियों में रोपी गयी प्याज की फसल की आवक शुरू होने के साथ इसकी कीमतों में नरमी का रुख दिख रहा है। प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतें आपूर्ति की कमी के कारण दिल्ली-एनसीआर के बाजार में महंगे बने हुए हैं। पिछले हफ्ते टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए थे, जबकि प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दलहन, प्याज, टमाटर और तिलहन जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के संबंध में कार्टेलिज़ेशन (व्यापरी समूहों की परस्पर गुटबंदी), जमाखोरी, सट्टा व्यापार आदि की निगरानी के लिए गठित समूह की 18 वीं बैठक यहाँ उपभोक्ता मामला विभाग के सचिव, अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कृषि मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, नाफेड, डीजीएफटी, विदेश मंत्रालय, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने इस समूह को आवश्यक खाद्य जिंसों के संदर्भ में मौजूदा परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है और कीमतों में स्थिरता के साथ गिरावट का रुख है। समूह ने निर्णय लिया कि देश भर में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उचित समय पर उचित नीतिगत हस्तक्षेप करने की सिफारिश की जा सकती है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि , ''सभी मुख्य सचिवों को सलाह दी जाएगी कि वे राज्य और जिला स्तर पर विशेष रूप से त्यौहारों के मौसम यानी दिसंबर, 2019 तक, प्याज, दालों, खाद्य तेलों और तिलहन आदि के थोक व्यापारियों, व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों के साथ नियमित बैठक करें।'' इसमें कहा गया कि एनसीआर राज्यों की पुलिस की समिति को दिल्ली की राज्य सीमाओं के पास व्यापारियों द्वारा स्टॉक की जमाखोरी पर नज़र रखने और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में नियमित बैठकें करनी चाहिए।

सितंबर महीने में निर्यात 6.57 प्रतिशत घटा, आयात में भी 13.58 प्रतिशत की गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का निर्यात सितंबर में 6.57 प्रतिशत घटकर 26 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, इंजिनियरिंग, चमड़ा, रसायन और रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से निर्यात में गिरावट का असर कुल निर्यात पर पड़ा। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार आयात भी 13.85 प्रतिशत घटकर 36.89 अरब डॉलर रहा। इससे सितंबर महीने में व्यापार घाटा कम होकर 10.86 अरब डॉलर पर रहा। पिछले साल सितंबर में व्यापार घाटा 14.95 अरब डॉलर था। कुल 30 प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में से 22 में गिरावट दर्ज की गई। रत्न और आभूषण, इंजिनियरिंग सामान और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 5.56 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत और 18.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

सितंबर महीने में तेल आयात 18.33 प्रतिशत घटकर 8.98 अरब डॉलर रहा जबकि गैर-तेल आयात 12.3 प्रतिशत घटकर 27.91 अरब डॉलर रहा। संचयी रूप से इस साल अप्रैल-सितंबर के दौरान निर्यात 2.39 प्रतिशत घटकर 159.57 अरब डॉलर जबकि आयात 7 प्रतिशत घटकर 243.28 अरब डॉलर रहा। स्वर्ण आयात भी आलोच्य महीने में 50.82 प्रतिशत घटकर 1.27 अरब डॉलर रहा।

सितंबर में वनस्पति तेल का आयात 13 प्रतिशत घटा :एसईए

नयी दिल्ली। एजेंसी

वनस्पति तेल का आयात सितंबर 2019 में पिछले साल इसी महीने की तुलना में 13 प्रतिशत घटकर 13.03 लाख टन रहा। पिछले साल का भारी स्टॉक बचा होने तथा मलेशिया के पाम ऑयल पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने से ऐसा हुआ है। उद्योगमंडल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एसईए ने बताया कि मलेशिया से होने वाले आयात पर रोक लगाये जाने के अनुमानों के बीच कई व्यापारी पाम तेल के आयात के लिए इंडोनेशिया का रुख कर रहे हैं। मलेशिया ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र में सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था। एसोसिएशन ने कहा, ''सरकार ने चार सितंबर से प्रभावी होने वाले मलेशियाई मूल के आरबीडी पामोलिन / पाम ऑयल पर पांच प्रतिशत का सुरक्षा शुल्क लगाया है। इसे देखते हुए, किसी भी स्थान से आने वाले कच्चे और परिष्कृत पाम तेल के बीच का शुल्क का अंतर 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है।' इसमें कहा गया है हालांकि, आरबीडी पामोलिन का आयात सितंबर में लगभग पूर्व के स्तर पर ही रहा पर मलेशिया से आयात की मात्रा पिछले महीने के आयात से एक तिहाई कम हो गई है। एसईए के कार्यकारी निदेशक बी.वी. मेहता ने वनस्पति तेल के आयात में गिरावट आने का कारण पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक तथा सुरक्षा शुल्क लगाये जाने को बताया। बयान में कहा गया, ''दूसरी बात यह है कि हाल ही में मीडिया में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में मलेशिया के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बाद मलेशिया से पाम तेल के आयात पर रोक लगाने के लिए कुछ कार्रवाई कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र में मलेशिया ने आरोप लगाया कि भारत ने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया है। उसके इस बयान पर भारत की ओर से कुछ प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई सामने आने की आशंका के कारण कई आयातक / प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां नवंबर-दिसंबर खरीद खेप के लिए मलेशिया के स्थान पर इंडोनेशिया का रुख कर रही हैं।'' सितंबर के दौरान वनस्पति तेलों (खाद्य और अखाद्य तेल दोनों) का आयात 13 प्रतिशत घटकर 13,03,976 टन रहा।एक साल पहले इसी माह यह 14,91,174 टन था। सितंबर 2019 में खाद्य तेल का आयात घटकर 12,54,443 टन रहा जो पिछले साल सितंबर में 14,22,003 टन था, जबकि अखाद्य तेल आयात समीक्षाधीन अवधि में पहले के 69,171 टन से घटकर 49,533 टन रह गया। एसईए ने एक बयान में कहा कि नवंबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान वनस्पति तेलों का कुल आयात तीन प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ 41.7 लाख टन हो गया। एसईए ने कहा कि नवंबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान, मलेशिया से आयातित पामोलीन पर कम शुल्क होने के कारण, रिफाइंड तेल (आरबीडी पामोलीन) का आयात बढ़कर 26,12,394 टन हो गया जो पिछले साल की इसी अवधि में 19,98,813 टन का हुआ था। इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल का आयात कम हुआ जो घटकर 1,09,69,087 टन रह गया जो आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,13,43,273 टन था। इसकी वजह से घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग में कमी आई। नवंबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान, आरबीडी पामोलिन के अधिक आयात के कारण, पाम तेल का आयात बढ़कर 86,30,680 टन हो गया है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 79,47,472 टन का हुआ था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हल्के तेल (सॉफ्ट आयल) का आयात घटकर 49,50,801 टन रह गया जो पूर्व वर्ष की समान अवधि में 53,94,614 टन का हुआ था।

करवा चौथ का पवित्र मंत्र

चंद्र को अर्घ्य दें तब जरूर बोलें

करवा चौथ एक नारी पर्व है। सुहागिन नारी का अपने पति की दीर्घायु और हर प्रकार के सुख-ऐश्वर्य की कामना के साथ किया गया निर्जल व्रत। ऐसे अनूठे व्रत हिंदू संस्कृति में ही हो सकते हैं। यह नारी पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व में दिनभर का उपवास करके, शाम को सुहागिनें करवा की कहानियां कहती-सुनती हैं। उसके पश्चात गौरा से सुहाग लेकर तथा उगते चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने सुहाग की अटलता की कामना करती हैं।

इस बार जब चंद्र को अर्घ्य दें तो यह मंत्र अवश्य बोलें....

करकं क्षीरसंपूर्णा तोयपूर्णमयापि वा।
ददामि रत्नसंयुक्तं चिरंजीवतु मे पतिः।
इति मन्त्रेण करकान्प्रदद्याद्विजसत्तमे।
सुवासिनीभ्यो दद्याच्च आदद्यात्ताभ्य एववा।।
एवं व्रतंया कुरूते नारी सौभाग्य काम्यया।
सौभाग्यं पुत्रपौत्रादि लभते सुस्थिरां श्रियम्।।

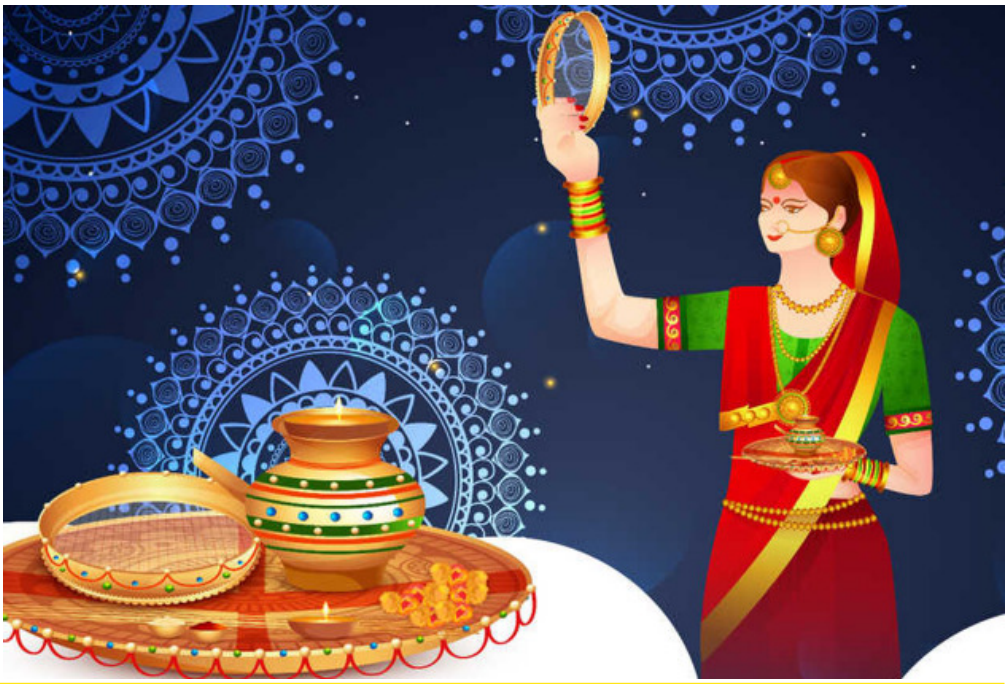

करवा चौथ पर गजकेसरी योग का संयोग, पूजन से होता है ऐसा लाभ

हिंदू संवत्सर के अनुसार जिस दिन सूर्योदय से लेकर अगले तीन घंटे तक जो तिथि होती है, उसे ही उस दिन की तिथि माना जाता है, भले ही इसके बाद दूसरी तिथि शुरू हो जाए। चूंकि इस बार 17 अक्टूबर को सूर्योदय पर तृतीया तिथि है, जो सुबह 6.48 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्योदय पर तृतीया तिथि होने के बावजूद इस दिन करवा चौथ मनाना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि करवा चौथ की पूजा के लिए चंद्रमा को देखकर पूजा करने की मान्यता है। 17 अक्टूबर की शाम को चंद्र दर्शन के समय चतुर्थी तिथि होने से इसी दिन करवा चौथ मनाया जाएगा। इस बार चंद्र दर्शन के दौरान गजकेसरी योग का संयोग बन रहा है। इस योग में पूजा करने से पति-पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होंगे।

वृद्धि तिथि के रूप में तृतीया तिथि

ज्योतिषाचार्य डॉ. दत्तात्रेय होस्केरे के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ मनाया जाता है। इस साल गुरुवार 17 अक्टूबर को तृतीया तिथि वृद्धि तिथि के रूप में सुबह 6.48 बजे तक ही है। इसके पश्चात चतुर्थी होने से इसी दिन करवा चौथ मनाया जाना श्रेष्ठ होगा।

मेष राशि में भद्रा का कोई प्रभाव नहीं

गुरुवार की रात चंद्र उदय का समय रात्रि 8.11 बजे है, चूंकि इस दिन मेष राशि का भद्रा है अतः यह निष्प्रभावी रहेगा, लेकिन सायंकाल 6.48 के बाद पूजन करना उचित होगा। इस दिन विशेष रूप से गणपति, गौरी की पूजा उपरांत विधिवत श्रीगणेश की स्थापना करके शिवजी का पूजन करने से दंपतियों की आयु, आरोग्यम और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी।

चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उच्च का

रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में पड़कर उच्च का हो रहा है। साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि होने के कारण गजकेसरी योग बन रहा है। इस योग में पूजा करना पति-पत्नी दोनों के लिए अत्यंत शुभ और प्रगतिकारक है।

पूजन का श्रेष्ठ समय

रात्रि - चंद्र दर्शन के दौरान रात्रि 8.11 बजे

पुष्य नक्षत्र में किए जाते हैं ये 8 फलदायक कार्य

ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा गया है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है। कहते हैं कि इस मुहूर्त में खरीदी गई कोई भी वस्तु अधिक समय तक उपयोगी, शुभ फल देने वाली और अक्षय होती है। पुष्य नक्षत्र किसी भी महीने में आए, त्योहार हो ना हो पर फिर भी इस दिन कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं या किसी भी प्रकार की खरीददारी की जा सकती है। आओ जानते हैं इस नक्षत्र में कौनसे 4 खास कार्य किए जाते हैं।

1.पुष्य नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं अतः इस दिन बृहस्पति का व्रत और पूजन किया जाता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है।

2.पीपल के पेड़ को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपने घर के खाली हिस्से में पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी पूजा करते हैं जिससे उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।

3.पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन इसलिए हैं, क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में माना जाता है और पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीदी अत्यधिक शुभ होती है। दीपावली के पूर्व आने वाला पुष्य नक्षत्र विशेष होता है, क्योंकि यह मुहूर्त खासतौर से खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है।

4.इस नक्षत्र में वाहन, भवन, भूमि और बहीखाते खरीदना भी शुभ होता है। इस दिन मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी प्रारंभ करना शुभ हैं।

5.इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय मां लक्ष्मी के सामने घी से दीपक जलाएं। किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत करें।

6.इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी की लड्डू आदि का सेवन भी किय जाता है और यथाशक्ति दान भी कर सकते हैं।

7.इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक खरीदना उत्तम माना जाता है। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें, जैसे ज्ञान या विद्या आरम्भ करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना, लेखक हैं तो कुछ नया लिखना आदि।

8.इसके अलावा पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लाकर उनकी सिद्धि की जाती है। इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को घटाया जा सकता है।

यदि पुष्य नक्षत्र सोमवार को आए तो उसे सोम पुष्य, मंगलवार को आए तो उसे भौम पुष्य, बुधवार को आए तो बुध पुष्य, गुरुवार को आए तो गुरु पुष्य, शुक्र को आए तो शुक्र पुष्य, शनि को आए तो शनि पुष्य और रवि को आए तो रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इनमें से गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम बताए गए हैं। सभी का फल अलग-अलग होता है।

करवा चौथ व्रत की खास बातें

करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन की जिंदगी संवार सकता है, लेकिन इसके लिए इस दिव्य व्रत से जुड़े नियम और सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए पढ़ें जरूरी बातें....

करवा चौथ का त्योहार इस बार 17 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ संतान सुख भी मिल सकता है। करवा चौथ के दिन श्री गणेश, मां गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दांपत्य सुख का वरदान मिलता है। विधि-विधान से ये पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है। करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के प्रयोग का फल निश्चित ही मिलता है।

करवा चौथ के व्रत में क्या करें और क्या ना करें

केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े कतई नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। ये व्रत निर्जल या केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं।

करवा चौथ व्रत की यह है सबसे सही और सरल विधि...मिलेगा पूरा फल

करवा चौथ के व्रत और पूजन की उत्तम विधि, जिससे इस प्रकार व्रत करने से आपको इस व्रत का 100 गुना फल मिलेगा। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। फिर मिठाई, फल, सेंवई और पूड़ी की सरगी ग्रहण कर व्रत शुरू करें। संपूर्ण शिव परिवार और श्रीकृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। उनके सामने मोगरा या चन्दन की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं। मिटटी के कर्वे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। कर्वे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें और रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार जरूर करें, इससे सौंदर्य बढ़ता है। इस दिन करवा चौथ की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए।

बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च चेतक नाम से वापसी की तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी

बजाज स्कूटर एक बार फिर से सडकों पर दौडने के लिए तैयार है। इसबार इलेक्ट्रिक स्कूटर रूप में लांच किया जाएगा। इसके फ्रंट और रीयर दोनों में डिस्क ब्रेक हो सकता है इसकी कीमत 60 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। बजाज ऑटो कंपनी अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर सकती है। दिल्ली में एक इवेंट के दौरान बजाज के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्दा उठेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल होंगे।

स्कूटर की दुनिया में बजाज की वापसी आज

दरअसल बजाज ऑटो के लिए यह स्कूटर बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। इस मौके पर कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक फ्यूचर को लेकर भी बड़े ऐलान होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजाज कंपनी की इस स्कूटर का नाम चेतक हो सकता है। इसका डिजाइन कंपनी के पुराने स्कूटर जैसा हो सकता है, जो रेट्रो लुक वाले स्कूटर की याद दिलाएगा। बजाज के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पिछले दिनों कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह स्कूटर रेट्रो डिजाइन के साथ स्पोर्टी लुक में है। फीचर्स की बात करें तो chetak chic के नाम के इस स्कूटर के फ्रंट और रीयर दोनों में डिस्क ब्रेक हो सकता है। स्कूटर के फ्रंट एंड पर एलईडी लैम्प हैं।

सेफ्टी के लिए स्कूटर में क्या-क्या खास

खबरों के मुताबिक बजाज चेतक चिक स्कूटर में सेफ्टी के लिहाज से इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) मिलेगा। इसमें बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल होगा, जिसमें बैटरी रेंज, ओडोमीटर और ट्रिपमीटर की जानकारी भी मिलेगी। स्मार्टफोन और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए यह इंस्ट्रूमेंट पैनल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करेगा। बजाज के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि 60 हजार रुपये के आसपास कीमत हो सकती है।

यादों में पुराना बजाज चेतक

बजाज ऑटो ने चेतक (Chetak) का प्रोडक्शन 2006 में बंद कर दिया था। चेतक स्कूटर को साल 1972 में पहली बार लॉन्च किया गया था। पिछले कुछ सालों से बजाज का पूरा फोकस बाइक्स बनाने पर हो गया है। लेकिन अब एक बार फिर कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ स्कूटर की दुनिया में वापसी कर रही है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले ट्रक, बस करेगी पेश

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रक एवं बस इकाई एमटीबीडी ने सोमवार को 16 टायर श्रेणी में ब्लाजो ट्रक की नयी श्रृंखला पेश की। कंपनी ने कहा कि वह अपने वाहनों को भारत स्टेज-6 उत्सर्जन मानक के अनुरूप बनाने के सही रास्ते पर है। कंपनी ने दावा किया कि वह मध्यम आकार के वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन कर उभरी है। कंपनी के वाहन कारोबार के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा, ''हम नयी सरल प्रौद्योगिकी पर आधारित बीएस-6 मानकों वाले ट्रकों और बसों की व्यापक श्रृंखला पेश करने के सही रास्ते पर हैं।'' उन्होंने कहा कि कंपनी की ट्रक एवं बस इकाई भी अपने ग्राहकों के लिए बीएस-6 मानकों को आसान बनाने की दिशा में काम रही है। उसके बीएस-4 मानक वाहनों के करीब 80 प्रतिशत कलपुर्जों को नए मानक लागू होने पर भी नहीं बदलना होगा।

डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई पर डीपीआईआईटी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विचार मांगे

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिये जाने के सरकार के फैसले को लेकर कुछ पक्षों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से उसके विचार मांगे हैं। सरकार ने अगस्त में प्रिंट मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया क्षेत्र में भी समाचारों और सम-सामयिक विषयों को अपलोड /प्रसारित करने के क्षेत्र में सरकारी मार्ग से 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दे दी। उद्योग से जुड़ी कुछ इकाइयों और विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा नियत किये जाने से कुछ सवाल उठे हैं जिसके बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है क्योंकि कुछ कंपनियां जो कि कोष जुटाने के बारे में सोच रही थीं उन पर प्रतिबंध लग सकता है। अधिकारी ने कहा, ''निर्णय को लेकर जो मुद्दे उठाये गये हैं, हमने उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा है। वे उपयुक्त स्पष्टीकरण को लेकर उस पर गौर कर रहे हैं।''उसने कहा कि क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी सरकारी मार्ग के जरिये दी गयी है, इसीलिए मंत्रालय से परामर्श मांगा गया है। डेलायॅट इंडिया के भागीदार जेहिल ठक्कर ने कहा था कि उन टेलीविजन प्रसारकों के मामले में किस तरह का व्यवहार होगा जो ऑनलाइन समाचारों का प्रसारण करते हैं लेकिन उन्हें 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। उन्होंने कहा कि उन समाचार वेबसाइट का क्या होगा जो 100 प्रतिशत विदेशी इकाई हैं? इंटरनेट एण्ड मोबाइल एसोसियेसन आफ इंडिया ने भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

भारत में 5जी उपकरण बनाने के लिए तैयार एरिक्सन

नयी दिल्ली। स्वीडन की दूरसंचार उपकरण वि निर्माता एरिक्सन ने घोषणा की है कि भारत में 5 जी सेवा के चालू होते ही वह देश में इसके लिए उपकरण बनाना शुरू कर देगी। एरिक्सन के प्रमुख (दक्षिण पूर्व एशिया , ओशिआनिया और भारत) नुनजिओ मिरतिलो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019 में कहा , ' इस साल हम यह कह सकते हैं कि एक बार देश में 5 जी शुरू हो जाएगा तो हम अपने उत्पादन को 4 जी से 5 जी में बदलने के लिए तैयार हैं। हम भारत के लिए , भारत में 5 जी उपकरणों का उत्पादन करेंगे। ' कंपनी ने कहा कि भारत में उसका कारखाना है, जहां 4जी नेटवर्क उपकरण बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहित करने वाली नीति, उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र और किफायती स्पेक्ट्रम कंपनियों को जल्द से जल्द 5जी सेवा शुरू करने में मदद करेंगे।

अफवाह फैलाने वाले संदेशों के स्रोत तक हो एजेंसियों की पहुंचः प्रसाद

नयी दिल्ली। एजेंसी

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विधि प्रवर्तन एजेंसियों के पास अफवाह और हिंसा फैलाने वाले संदेशों के स्रोत तक पहुंच होनी चाहिए। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कूटेलखन या एन्क्रिप्शन का सम्मान करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2019 को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा, ''हम एन्क्रिप्शन का सम्मान करते हैं लेकिन जब अफवाह फैलाने के संदेश एक ही समय, एक ही क्षेत्र और एक ही मुद्दे पर बार-बार आगे बढ़ाएं जाएं, तो निश्चित रूप से इसके स्रोत का पता लगना चाहिए ताकि इनसे निपटा जा सके।'' मंत्री ने कहा, ''इंटरनेट स्थिर और सुरक्षित होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए।'' संदेश तक पहुंच या पहचान सरकार और मैसेजिंग कंपनी व्हॉट्सएप के बीच विवाद का प्रमुख मुद्दा है। फेसबुक की इकाई व्हॉट्सएप अभी तक संदेश के मूल स्रोत तक पहुंच की भारत की मांग पूरी नहीं कर रही है। व्हॉट्सएप की दलील है कि इससे गोपनीयता की नीति और कूटलेखन प्रभावित होगा। सूत्रों ने कहा कि फेसबुक के वैश्विक मुख्य कार्यकारी निक क्लेग ने पिछले महीने प्रसाद के साथ बैठक में संदेशों तक पहुंच के विकल्प रखे थे। इसमें इस मुद्दे से निपटने का 'मेटा डेटा' और मशीन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। यहां तक कि उन्होंने विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग के लिए व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के संपर्क उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। अपने संबोधन में प्रसाद ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आंकड़ों का सृजन कर रहा है। उन्होंने कहा, ''मैं चाहता हूं कि भारत डेटा के विश्लेषण, शोधन और उसे परिष्कृत करने का बड़ा केंद्र बन सके।'' मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा गोपनीयता, डेटा नवोन्मेष और डेटा उपयोग के बीच संतुलन कायम किया जाए।

वेयरहाउसिंग कारोबार पर जीएसटी को लेकर 70 प्रतिशत किरायेदार आशावादी

नयी दिल्ली। वेयरहाउसिंग (भंडारण सुविधा) कारोबार पर एक ताजा सर्वेक्षण रपट में कहा गया है कि कारोबारी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को इस क्षेत्र के अनुकूल मानते हैं इस क्षेत्र में घरेलू व विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है। रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी सीबीआरई साऊथ एशिया प्रायवेट लिमिटेड की मंगलवार को जारी इस सर्वेक्षण रपट में कहा गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद 2017 से 2019 की पहली छमाही तक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग में 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा के निवेश किए गए हैं। 'एक देश-एक कर' व्यवस्था के प्रभाव पर इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और नवीन उद्यम नीतियों के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि की बढ़ावा मिल रहा है। सीबीआरआई की विज्ञप्ति के मुताबिक इस सर्वेक्षण में शामिल 80 प्रतिशत प्रतिभागियों को लगता है कि जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था में सुधार हुए हैं। इसमें 40 प्रतिशत लोगों ने बताया कि जीएसटी के बाद वे वेयरहाउस की संख्या को बढ़ाना चाहेंगे। इसी तरह 60 प्रतिशत से अधिक ने बताया कि जीएसटी के बाद वे अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं के साथ अच्छी साझेदारी या संयुक्त उपक्रम को प्राथमिकता दे रहे हैं। सीबीआरई के भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुमान मैगज़ीन ने कहा, 'भारत में लॉजिस्टिक्स उद्यम में परिवर्तनकारी वृद्धि हो रही है। परिचालन में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नए कारोबारी मॉडल और नीतियां, आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं में सुधार आदि से वेयरहाउसिंग के लिए मांग में बढ़ोतरी हुई है। हमारा अनुमान है कि प्रमुख कम्पनियां इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक है और इस वजह से देश की वेयरहाउसिंग सुविधाओं में 2030 तक 50 करोड़ वर्ग फुट तक बढ़ोतरी होगी।' सर्वे के अनुसार करीबन 70 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कारोबार सुगमता में सुधार हुए हैं। ई-वे बिलिंग से भंडारण और आवागमन प्रक्रिया की कई समस्याओं को दूर किया गया है। रपट के अनुसार औद्योगिक एवं लाजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग की मांग 2018 की अपेक्षा 10 से 15 प्रतिशत से बढ़ेगी और 2019 में करीबन 2.5 से 3 करोड़ वर्ग फुट जगह पट्टे पर दी जाएगी। बड़ी कंपनियों के इस क्षेत्र में आने से देश में वेयरहाउसिंग स्टॉक 2030 तक 50 करोड़ वर्ग फुट तक बढ़ेगा।

ई-कॉमर्स कंपनियों की बदौलत कार्गो फ्लाइट को मिली पहली उड़ान

वाटर सैल्यूट से हुआ वेलकम, जल्दी ही होगी रेग्यूलर कार्गो सर्विस

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

निजी एयरलाइंस स्पाइस जेट ने इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डे पर पहली बार कार्गो विमान सेवा शुरू की। इस विमान में फिलहाल ई कॉमर्स कंपनियों का माल ही जा रहा है। ई-कामर्स डिलिवरी की वजह से यह सेवा शुरू हो पाई है। इधर इस उड़ान को नियमित करने और अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ान शुरू करने की मांग भी शुरू हो गई है।जानकारी के अनुसार सुबह साढ़े 6 बजे विमान दिल्ली से इंदौर आया। यहां विमानतल निदेशक अर्यमा सान्याल और अन्य अधिकारियों ने उसका स्वागत किया। परंपरा के अनुसार विमान को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। इसके बाद विमान में आए पायलेट और अन्य स्टाफ का स्वागत किया गया।

इंदौर से साढ़े 7 बजे उड़ान भर विमान अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। प्रबंधन सूत्रों के अनुसार स्पाइसजेट ने अपनी कार्गो सेवा को स्पाइस एक्सप्रेस नाम दिया है। इसे प्रयोग के तौर पर 25 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अच्छा प्रतिसाद मिलने पर कंपनी इसे नियमित कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि इस विमान में ई-कॉमर्स कंपनियों का माल अहमदाबाद, पुणे और बैंगलुरू के लिए रवाना हुआ। कई ई-कॉमर्स वेबसाइट ने हाल ही में अपनी सेल खत्म की है और अगले सप्ताह से फिर से नई सेल आने वाली है। इनकी एक्सप्रेस डिलेवरी के लिए स्पाइस जेट ने यह विशेष विमान चलाया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ट्रकों की हड़ताल के कारण इन कपंनियों को मध्यप्रदेश में 170 करोड़ के आर्डर निरस्त करना पड़े थे।

इधर इस उड़ान को नियमित करने के लिए प्रबंधन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह एयरलाइंस, एएआई कार्गो लॉजिस्टिक और शहर के बड़े वेयर हाउस संचालकों, कारोबारियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के लोगों की एक बैठक भी बुलाई गई है। इसमें इस उड़ान को नियमित करने पर चर्चा की जाएगी।

फार्मा सेक्टर से ही चल जाएगी उड़ान

बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश के सचिव ने बताया कि जब से दुबई उड़ान शुरू हुई है, हम लोग अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ान शुरू करने की मांग कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में हर साल करोड़ों का आयात-निर्यात होता है। कच्चा माल हम चीन से मंगवाते हैं। यह मुंबई होकर आता है। इसमें काफी देरी होती है जबकि यहां से तैयार माल दुबई, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस के लिए जाता है। इसमें भी माल को पहले मुंबई भेजा जाता है। अगर सीधी उड़ान हुई तो काफी सुविधा होगी। अगर कार्गो उड़ान शुरू हुई भी तो फार्मा सेक्टर से ही वह पूरी लोड हो जाएगी।

मध्यप्रदेश के इंदौर सेज से निर्यात सात प्रतिशत बढ़ा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरूआती छह महीनों (अप्रैल से सितंबर) के दौरान मध्यप्रदेश के इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) से निर्यात सात फीसद की बढ़त के साथ 5,022 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 4,691 करोड़ रुपये का था। इंदौर सेज के एक अधिकारी ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी को बताया, 'अप्रैल से सितंबर के बीच इंदौर सेज से हुए निर्यात में 50 फीसद से ज्यादा भागीदारी दवाओं की रही।' अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इंदौर सेज में फार्मा, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग, वस्त्र निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण समेत अलग-अलग क्षेत्रों की 60 इकाइयां चल रही हैं। सेज में पांच नई इकाइयों का निर्माण चल रहा है। यह सेज हालांकि पड़ोसी धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में स्थित है। लेकिन 1,100 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैली इस जगह को आधिकारिक तौर पर 'इंदौर सेज' के नाम से ही जाना जाता है।

सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिये नौ शहरों में 14 कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता (एमएसडीई) मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए भारत के 9 शहरों में 14 अधिकृत विश्व कौशल भारत प्रशिक्षण केंद्र (एडब्ल्यूएसआईटीसी) शुरू करने की घोषणा की। नए संस्थान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में न केवल विश्व कौशल और भारत की कौशल प्रतियोगिताओं से मुकाबला करने के लिए उम्मीदवारों को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं बल्कि इनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल परिवेश विकसित करना भी है। पांडे ने कहा, "...ग्राफिक डिजाइन, 3 डी डिजिटल गेम आर्ट, प्रिंट मीडिया आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल प्राप्त लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं हैं। विश्व स्तर के आधुनिक केंद्र उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश को गौरव दिलाने के लिए तैयार करने में मदद करेंगे और लाभकारी तरीके से कार्य करने के लिए उनका कौशल बढ़ाएंगे।'प्रशिक्षण केंद्रों पर ग्राफिक डिजाइन तकनीक, 3 डी डिजिटल गेम और प्रिंट मीडिया प्रौद्योगिकी पर 9 महीने से 36 महीने की अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।

MEDIA & ENTERTAINMENT SKILLS COUNCIL

500 अरब डॉलर के फूड रिटेल मार्केट में फ्लिपकार्ट लेगी एंट्री

मुंबई। एजेंसी

वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट फूड रिटेल सेगमेंट में उतर रही है। भारतीय उपभोक्ता किराने के सामान पर सालाना 500 अरब डॉलर खर्च करते हैं। फ्लिपकार्ट फार्मरमार्ट हाल ही में 1,845 करोड़ रुपये के इक्विटी कैपिटल के साथ रजिस्टर हुई है। वह देश में बनने वाले सामान बेचेगी। इसके माध्यम से पहले ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर बिक्री की जाएगी। कंपनी बाद में ऑफलाइन स्टोर भी खोल सकती है।

फ्लिपकार्ट ग्रुप के एंड कल्याण कृष्णमूर्ति ने बताया, 'सरकार की इअ (फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) पॉलिसी फूड रिटेल में घरेलू उत्पादित सामान पर 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की इजाजत देती है। फ्लिपकार्ट इसके लिए सरकार से लाइसेंस पाने की कोशिश कर रही है। हमें सभी इंटरनल अप्रूवल मिल चुके हैं।' फ्लिपकार्ट फार्मरमार्ट फूड रिटेल पर जोर देते हुए देश की ऐग्रिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है।

कृष्णमूर्ति ने बताया, 'हम लोकल ऐग्री ईकोसिस्टम और सप्लाई चेन में निवेश करना चाहते हैं। हम लाखों छोटे किसानों और फार्म प्रड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन्स (इइ) के साथ मिलकर देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्राहकों तक किफायती और अच्छा सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी।'

वॉलमार्ट भारत में उपभोक्ताओं को सीधे सामान नहीं बेचती है। वह देश में किराना दुकानों, होटलों और केटरिंग फर्मों के ऑर्गनाइज्ड होलसेलर या कैश-ऐंड-कैरी ऑपरेटर के तौर पर काम करती है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर ने देश के 670 अरब डॉलर के रिटेल मार्केट में उतरने के लिए 2017 में फ्लिपकार्ट को 16 अरब डॉलर में खरीदा था।

फूड इकलौता सेगमेंट है, जिसमें ईटेलर्स को उपभोक्ताओं को सीधे सामान बेचने की अनुमति है। सरकार ने 2016 में फूड-रिटेल सेगमेंट बनाने के लिए मल्टी ब्रांड रिटेल में इअ की अनुमति दी थी। सरकार का कहना था कि इससे रोजगार बढ़ेगा और किसानों की मदद होगी। हालांकि, ई-कॉमर्स कंपनियों को उनकी फूड रिटेल इकाई को फ्लैगशिप मार्केटप्लेस से अलग रखने को कहा गया है। इसके लिए अलग बोर्ड, स्टाफ, बैंक अकाउंट और इन्वेंटरी होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने बताया, 'इससे किसानों से डायरेक्ट सामान खरीदने और फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के मौके बनेंगे।' उन्होंने कहा, 'मंत्रालय किसानों की आय दोगुनी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करना चाहता है।' कौर ने बताया कि फ्लिपकार्ट ने अब तक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटरनल ट्रेड (अइछऊ) में अर्जी नहीं भेजी है। कंपनी के टॉप एग्जिक्यूटिव्स ने बताया कि नई फर्म को फ्लिपकार्ट के बोर्ड से पिछले महीने ऐप्लिकेशन आगे भेजने की मंजूरी मिल चुकी है।

कंसल्टेंसी फर्म थर्ड आईसाइट के चीफ एग्जिक्यूटिव देवांग्शू दत्ता ने बताया, 'इस पहल से वॉलमार्ट की भारतीय मार्केट में दिलचस्पी का अंदाजा लगता है। रिटेल में फूड की हिस्सेदारी अच्छी है। इसमें विस्तार करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, सप्लाई चेन तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा।'

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।